(c) the efforts made so far to provide licences to the entrepreneurs belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for colour TVs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, SPACE AND ELECTRONICS (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) No, Sir. The licences for the manufacturing of CTV sets are now being given for all the permissible locations in Delhi.

(b) Does not arise.

(c) There is no separate industrial and licensing policy for CTV sets for Scheduled Castes/Scheduled Tribes. All applications are considered as per the Industrial and Licensing Policy for CTV sets announced on February 25, 1983.

पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति

538. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री कैलाशपति मिश्र :
श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों की पहचान किये जाने की कसौटी क्या है और इन क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या राज्यवार कितनी कितनी है ;

(ख) गत छः पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ में तथा अन्त में यह संख्या कितनी-कितनी थी और सातवीं योजना के अन्त में कितनी होने की संभावना है ; और

(ग) इस प्रकार के व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए वर्ष 1985-86 के लिए राज्यवार निर्धारित लक्ष्य क्या-क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) गरीब व्यक्तियों की परिभाषा में वे लोग आते हैं जिनका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1977-78 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 65 रु० और शहरी क्षेत्रों में 75 रु० से कम है। यह क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी के दैनिक उपभोग और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी के दैनिक उपभोग के अनुरूप है।

गरीबी की रेखा की संकल्पना और इससे नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के प्रतिशत का अनुमान पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना (1080—85) के लिए लगाये गये थे। ये योजना आयोग द्वारा वर्ष 1977 में स्थापित "न्यूनतम आवश्यकताओं तथा प्रभावी उपभोग/मांग" से सम्बन्धित कार्यकारी दल (टास्क फोर्स) की सिफारिशों पर आधारित थे। इन अनुमानों के आंकड़ों का मुख्य स्रोत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण है।

छठी योजना के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन के वर्ष 1977-78 के सर्वेक्षण पर आधारित हैं। यह सर्वेक्षण अन्तिम उपलब्ध सर्वेक्षण है। वर्ष 1977-78 के लिए अनुमान (ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के लिए राज्यवार आंकड़े) संलग्न हैं।

छठी योजना के आधार वर्ष (1979-80) के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के आधार पर लगाये गये हैं जो नीचे दिए गए हैं :—

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या

(मिलियन)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	कुल
1979-80	273.0 (53.6 प्रतिशत)	65.0 (42.9 प्रतिशत)	339.0 (51.1 प्रतिशत)

छठी योजना की अवधि में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान वर्ष 1983 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित होगा। ये परिणाम तैयार किये जा रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या के बारे में इस समय बताना संभव नहीं है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं फिर भी जैसा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के नीति पत्र में परिकल्पना की गई है, गरीबी दूर करने के लिए सभी कार्यक्रम सातवीं योजना में और भी तेज गति से कार्यान्वित किये जाते रहेंगे।

विवरण

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्यवार अलग-अलग संख्या और प्रतिशत—1977-78

क्र० सं०	राज्य	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
		संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत
1		2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	170.35	43.89	36.44	35.68	206.79	42.18
2.	असम	88.34	52.65	7.07	37.37	95.41	51.10
3.	बिहार	338.44	58.91	32.94	46.07	371.38	57.49
4.	गुजरात	94.84	43.20	26.48	29.02	121.32	39.04
5.	हरियाणा	22.10	23.25	6.95	31.74	29.05	24.84
6.	हिमाचल प्रदेश	10.37	28.12	0.51	16.56	10.88	27.23
7.	जम्मू और कश्मीर	14.57	32.75	4.35	39.33	18.92	34.06
8.	कर्नाटक	124.10	49.88	38.62	43.97	162.72	48.34
9.	केरल	93.42	46.00	22.19	51.44	115.61	46.95
10.	मध्य प्रदेश	244.59	59.82	42.74	48.09	287.33	57.73
11.	महाराष्ट्र	214.11	55.85	61.30	31.62	275.41	47.71
12.	मणिपुर	3.42	30.54	0.56	25.48	3.98	29 71
13.	मेघालय	5.51	53.87	0.36	18.16	5.87	48.03
14.	नागालैंड	उ० न०	उ० न०	0.03	4.11	उ०न०	उ०न०
15.	उड़ीसा	158.97	68.97	10.33	42.19	169.30	66.40
16.	पंजाब	13.49	11.87	9,59	24.66	23 08	15.13
17.	राजस्थान	85.79	33.75	19.12	33.80	104.91	33.76

1	2	3		4	5	6	7
18.	तमिलनाडु	170.47	55.68	66.59	44.79	237.06	52.12
19.	त्रिपुरा	10.93	64.28	0.61	26.34	11.54	59.73
20.	उत्तर प्रदेश	429.93	50.23	72.27	49.24	502.20	50.09
21.	पश्चिम बंगाल	227.65	58.94	48.10	34.71	275.75	52.54
22.	सभी संघ राज्यक्षेत्र	6.35	34.32	11.24	17.96	17.59	21.69
	अखिल भारतीय (भारित)	2527.74	50.82	518.39	38.19	3046.10	48.13

उ० न० उपलब्ध नहीं :

नोट : (1) उपर्युक्त अनुमान वर्ष 1977–78 की कीमतों के आधार पर 65 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास की गरीबी की रेखा का उपयोग करते हुये प्राप्त किये गये हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 400 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के अनुसार है, 75 रु० की गरीबी की रेखा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता के अनुसार है। इनका अनुमान अखिल भारतीय आधार पर लगाया गया है।

(2) ये परिणाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के 32वें दौर (जुलाई, 1977 से जून, 1978) से सम्बन्धित अनन्तिम और त्वरित सारणीयन पर आधारित है।

(3) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में दिए गए अखिल भारतीय निजी उपभोक्ता व्यय से सम्बन्धित कुल अनुमानों और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों से प्राप्त कुल अनुमानों में जो अन्तर है उसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित करने के सम्बन्ध में किसी सूचना के अभाव में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यथा अनुपात समायोजित किया गया है।

(4) गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों की संख्या 1 अक्तूबर, 1972 और 1 मार्च, 1978 की जनसंख्या से सम्बन्धित है।

(5) अखिल भारतीय आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या उन राज्यों की जनसंख्या के अनुसार है, जिन्हें विवरण में शामिल किया गया है।

Document relating to demarcation of Hindi and Punjabi Regions of the undivided State of Punjab

539. SHRI SULTAN SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any document with the Ministry of Home Affairs signed by Shri Devi Lal, Prof. Sher Singh, Giani Kartar Singh, Sardar Harcharan Singh Hardia or Sardar Ajmer Singh, to demarcate the Hindi and Punjabi regions of Punjab, at the time of acceptance of regional formula by the Central Government under which the State was divided into two regions—Hindi and Punjabi and two regional committees were formed;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether a copy of the award given by Shrimati Indira Gandhi in 1970 on Chandigarh, Abohar and Fazilka is proposed to be laid on the Table of the House?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) and (b) Presumably the reference is